



## RECPDCL ने राजस्थान पावर प्रोजेक्ट को Apraava को हस्तांतरित किया

### चर्चा में क्यों?

**REC लिमिटेड** की सहायक कंपनी **REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (RECPDCL)** ने राजस्थान IV-A पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट अपरावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (**Apraava Energy Private Limited- AEPL**) को हस्तांतरित कर दी।

- यह परियोजना राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा ज़ोन फेस IV से वदियुत की निकासी को सुवधाजनक बनाने हेतु तैयार की गई है, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर परिसर शामिल हैं।

### मुख्य बढि

#### ■ राजस्थान IV-A पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट:

- प्रोजेक्ट का दायरा:
  - 765/400 kV, 4x1500 MVA पूलिंग स्टेशन का निर्माण।
  - 400/220 kV, 5x500 MVA पूलिंग स्टेशन का निर्माण।
  - 400 kV ट्रांसमिशन लाइन की 184.56 किलोमीटर की लाइन बछिआई जाएगी।
- समय-सीमा: इस परियोजना के दो वर्ष के भीतर पूरा होने की आशा है।
- क्षमता वृद्धि: इस परियोजना से क्षेत्र की वदियुत संचरण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- प्रभाव: यह परियोजना राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों का समर्थन करेगी।
- महत्त्व: यह हस्तांतरण वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित वदियुत क्षमता हासिल करने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है।
- मॉडल का प्रकार: इस परियोजना को **नरिमाण-परचालन-हस्तांतरण (Build, Own, Operate, and Transfer- BOOT)** के आधार पर विकसित किया जाएगा। यह विकास क्षेत्र में वदियुत संचरण बुनियादी ढाँचे को बढाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - **BOOT** मॉडल एक प्रकार का ऑपरेटर मॉडल है जिसका उपयोग परियोजना प्रबंधन में किया जाता है। इस मॉडल में वास्तविक निवेशक किसी परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव को सीमित समय के लिये किसी अन्य कंपनी को सौंपता है।

## भारत का स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य

- भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुँचना और वर्ष 2030 तक अपनी बिजली आवश्यकताओं का पचास प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना है।
- वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को इस दशक में ऊर्जा मांग में अधिकांश वृद्धि को पहले से ही कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना होगा।
- भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और एक अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना शामिल है।

